Title: Need to protect the interests of indigenous industries.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, वर्तमान औद्योगिक नीति से सार्वजनिक उपक्रमों के श्रमिकों में भारी असंतोा फैला हुआ है। श्रमिकों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो उद्योग घाटे में चल रहे थे, उनको लाभ में लाने का प्रयास किया है और अब ये उद्योग लाभ में परिवर्तित हो गए हैं। विदेशी कंपनियों को कस्टम-ऐक्साइज़ ड्यूटी में छूट एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर स्वदेशी उद्योग एवं सरकारी उपक्रमों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि जो उपक्रम कंपनी लेबल पर लाभ में चल रहे हैं, उनको शेयर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अधिकारियों एवं मजदूरों में जागृति आई है और उद्योग को चलाना वे अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। सरकार से मेरी मांग है कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाए क्योंकि निजीकरण को महत्व देने के कारण सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारी एवं श्रमिक यह महसूस करते हैं कि अधिक काम करने के बावजीद भी उनकी कार्यकुशलता पर शक किया जाता है जिस कारण उनका मनोबल गिरता है। मैं चाहता हूं कि इन उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों एवं प्रबंधकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन उपक्रमों को यथावत् चालू रखा जाए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाए।

15.00 hrs.